

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक R-2042-तीन/06

जिला - अशोकनगर

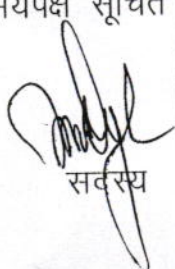
स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.6.16	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 245/05-06/अपील में पारित आदेश दिनांक 26-6-06 विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को प्रचलन योग्य न मानकर अस्वीकार किया गया है ।</p> <p>2/ प्रकरण में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उनके द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 57 (2) के तहत व्यवस्थापन का आवेदन दिया गया । इस पर से अनुविभागी अधिकारी ने व्यवस्थापन के आदेश विधिवत कार्यवाही करने के उपरांत दिये । कलेक्टर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया गया । जिसके विरुद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील की । अपील पर सुनवाई के दौरान आवेदक ने मौखिक निवेदन पर अपील को निगरानी में परिवर्तित का अनुरोध किया, जिसे अनदेखा करते हुए अपर आयुक्त ने आवेदक की अपील को निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।</p> <p>3/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया गया आवेदक द्वारा कोई आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में अपील को निगरानी में परिवर्तित करने हेतु नहीं दिया गया है । अतः अधीनस्थ</p>	

R
ajsc



R-2042-III/06

(अशासनग)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>न्यायालय का आदेश उचित है ।</p> <p>4/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक के पक्ष में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किए गए व्यवस्थापन को कलेक्टर ने स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया गया था, अतः उक्त आदेश अपील न होकर निगरानी योग्य था किंतु आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील की गई जिसे अपर आयुक्त ने प्रचलन योग्य न मानकर निरस्त किया है । आवेदक अधिवक्ता का यह कहना कि उनके द्वारा मौखिक निवेदन अधीनस्थ न्यायालय में अपील को निगरानी में परिवर्तित करने हेतु किया गया था, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा मौखिक या लिखित रूप से अपील को निगरानी में सुनने बावत कोई मांग नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।</p> <p>परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हो एवं अभिलेख वापिस हों ।</p>	<p style="text-align: center;">  सदस्य </p>

R
1/12